HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

The 18th October, 1983

No. 28HA/63-5/4349.—In pusrusance of provisions of Section 48 of the Land Acquisition Act, 1894 and and all other powers enabling in this behalf the Governor of Haryana hereby withdraws from the acqeuisition of land specified below with respect to which a notification under Section 4 of the said Act, was issued,—*vide* Haryana Government notification No. 28HA/63-5/931, dated 12th January, 1979 published in *Haryana Government Gazette*, dated 23rd January, 1979, for the Scheme of Constructing PWD, B&R Store, Godown and Offices at Dabwali in Sirsa District.

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area in Acres	Boundary
Sirsa	Dabwali	Dabwali	278	4.00	642, 653/1

No. 28HA/63-5/4350.—In pursuance of the provisions of Section 48 of the Land Auquisition Act, 1894., and all other Powers enabling in this behalf, the Governor of Haryana hereby withdraws from the acquisition of land specified below with respect to which a notification under Section 6 of the said Act, was issued,—*vide* Haryana Government notification No. 28HA/63-5/1160, dated 12th January, 1982 published in Haryana Gazette, dated 12th Janunary, 1982, for the Scheme of constructing PWD, B&R Store, Godown and Offices etc. at Dabwali in Sirsa disrtrict.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area in Acres	Boundary
Sirsa	Dabwali	Dabwali	278	4.00	642, 653/1

(Sd.) . . .,
Superintending, Engineer,
Hissar Circle, PWD, B&R Hissar.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 14 अक्तूम्बर, 1983

सं० ओ.वि./एफ.डी./248-83/55897.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैसर्ज क्वालटी इंडस्ट्रीयल बर्कस 17, जी. एन. आई. टी. फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद हैं;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (I) खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामलें, जो उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच का तो विवादग्रस्त मामला (मामलें) है/हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामलें) है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है:—

क्या श्रमिक वर्ष 1982-83 के बौनस 20 प्रतिशत की दर से हकदार है? यदि नहीं है तो कितने प्रतिशतबोनस के हकदार है ?